

बनाम

सरकार जरिये उप तहसीलदार पाटन जिला सीकर

रेसपोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 09.01.2018 मु.न. 243/2017 अनुवानी
सरकार बनाम राजकुमार द्वारा न्यायालय उप तहसीलदार पाटन

वकील अपीलांट श्री लक्ष्मण सिंह सुण्डा

निर्णय

दिनांक:-27.06.2019

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पाटन ने अधिनस्थ उप तहसीलदार पाटन के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि अपीलान्त ने भूमि खसरा नम्बर 811 वाके ग्राम पाटन में पुख्ता दुकान बना रखी है। उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के नाम नोटिस जारी किया। जिस पर अपीलान्त दिनांक 7.12.2017 को योग्य अधिनस्थ उप तहसीलदार पाटन के समक्ष अपस्थित हुआ और अपीलान्त ने इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया कि अपीलान्त का विवादग्रस्त भूमि पर उसके पिता बैधनाथ जी के जीवनकाल से कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलान्त का बड़ा भाई राजकुमार जो बैधनाथ का बड़ा पुत्र है उसके नाम से ग्राम पंचायत पाटन द्वारा दिनांक 05.08.1980 को 400 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी किया गया है और अपीलान्त व उसके भाई ने पट्टा शुदा भूमि में मकान व तीन दुकाने बना रखी है। जिस पर योग्य अधिनस्थ उप तहसीलदार पाटन ने अपीलान्त को मौके पर आकर निर्णय किए जाने हेतु कहा व दिनांक 07.12.2017 को आगामी कोई तारीख पेशी नहीं बताई और अपीलान्त को बिना साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का मौका दिए बिना ही व स्वयं उप तहसीलदार द्वारा मौके पर आये बिना ही दिनांक 09.01.2018 को अपीलान्त की अनुपस्थिति दर्ज करते हुये अपीलान्त को विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने हेतु अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलान्त के बड़े भाई राजकुमार के हक में ग्राम पंचायत पाटन द्वारा जारी पट्टा नं० 04 दिनांक 05.08.1980 की भूमि पर अपीलांट व उसके भाईयों ने पुख्ता तीन दुकाने व मकानात बना रखे है। अपीलांट का कब्जा विवादग्रस्त भूमि पर सन् 1974 से अपने पिता बैधनाथ के समय से निरन्तर चला आ रहा है। जिसमें अपीलान्त ने विधुत सम्बन्ध भी ले रखा है। भूमि खसरा नम्बर 811 के पूरे रकबे पर काफी वर्षों पूर्व से करीब 30 दुकाने बनी हुई है व काफी लोगो के आवासीय मकानात बने हुये है। मौके पर उक्त भूमि खसरा नम्बर 811 गो०मु० पहाड़ के रूप में न तो कभी पूर्व मे रही है और न अब भी मौके पर कोई पहाड़ है। अपीलान्त का कब्जा सन् 1974 से निरन्तर चला आ रहा होने से उक्त भूमि आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत के आधिपत्य में होने से ग्राम पंचायत पाटन ने अपीलान्त के हक में मिसल नं. 3 दिनांक 25.01.1974 की पालना मे पट्टा सं० 04 दिनांक 05.

08.1980 20 गुणा 20 गज अर्थात 400 वर्गगज भूमि का जारी किया है। अपीलान्त व उसके भाईयों का कब्जा उसकी पट्टाशुदा भूमि पर है व उसी पर अपीलान्त ने मकान व दुकान बना रखे हैं। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने चुनौतिग्रस्त निर्णय में यह मानने में कानूनी गलती की है कि ग्राम पंचायत को गेर मुमकिन पहाड़ की भूमि का पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं है, जबकि अपीलान्त के बड़े भाई राजकुमार के हक में जारी पट्टे के सम्बन्ध में आज तक किसी ने कोई आपत्ति नहीं की और न ही उक्त पट्टा आज तक निरस्त किया गया है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार पाटन ने न तो स्वयं ने कोई मौका मुआयना किया और न ही अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत जवाब के बाद कोई मौके की रिपोर्ट मंगवाई और अपीलान्त को साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का मौका दिये बिना ही अपीलान्त की अनुपस्थिति बताते हुये अपना निर्णय जेर अपील दिनांक 09.01.2018 पारित कर दिया गया, जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार पाटन का निर्णय जेर अपील दिनांक 09.01.2018 को अपास्त किए जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

अधिवक्ता अपीलांत की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांत को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। अपीलांत निर्धारित तारिख पेशी पर सक्षम न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ एवं जवाब नोटिस पेश कर जवाब में अंकित किया कि ग्राम पाटन में स्थित भूमि खसरा नम्बर 811 में प्रार्थी का पुराना कब्जा है तथा ग्राम पंचायत पाटन द्वारा दिनांक 05.08.1980 को प्रार्थी के नाम से पट्टा जारी किया हुआ है। उक्त पट्टाशुदा भूमि पर प्रार्थी ने मकान व दुकान बना रखी है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांत द्वारा ग्राम पाटन के खसरा नम्बर 811 रकबा 6.09 है० किस्म गै.मु.पहाड़ में से 24 वर्गमीटर पर दो दुकान बना कर अतिक्रमण कर रखा है। गै.मु.पहाड़ की भूमि राजकीय भूमि है। जिस पर प्रार्थी/अपीलांत को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। उपरोक्त आराजियात पर अतिक्रमण नहीं होने के सम्बन्ध में अपीलांत द्वारा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे यह साबित किया जा सके कि विवादित स्थल पर अपीलांत का कोई अतिक्रमण नहीं है। अतः राजकीय भूमि (गै.मु. पहाड़) पर दुकान बनाकर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार पाटन के द्वारा बेदखली आदेश दिनांक 09.01.2018 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांत खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश) 27/6/19

अति० जिला कलक्टर, सीकर